



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)फ्रैम
18/9

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 21, 2002/माष 1, 1923

No. 40]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 21, 2002/MAGHA 1, 1923

महानिदेशक (रक्षोपाय) का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2001

विषय : सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली के नियम 18 के अधीन (यहाँ एस जी डी के रूप में संदर्भित) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख के अधीन अधिसूचित विकासशील देशों से भारत में फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का पुनरीक्षण—अंतिम निष्कर्ष।

सा.का.नि. 50(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 एवं सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए।

(क) प्रस्तावना

रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 6 के अधीन भारत में फिनाल के आयात के संबंध में जॉच शुरू करने का नोटिस 2-2-99 को जारी किया गया था। फिनाल के वर्धित आयात से गंभीर क्षति की आशंका से घरेलू उधोग को बचाने के लिए फिनाल के आयात पर न्यूनतम रक्षोपाय आवश्यक रामाझी गई जो कि प्रथम वर्ष के दौरान यथामूल्य 22% और दूसरे वर्ष के दौरान यथामूल्य 15% की दर से रक्षोपाय शुल्क लगाने की संस्तुति करने संबंधी अंतिम निष्कर्ष कथित नियमावली के नियम 11 (1) के अधीन (भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II खंड-III उपखण्ड (i) में प्रकाशित) दिनांक 11-6-99 को जारी किए गए थे। रक्षोपाय नियमावली के नियम 12 एवं 14 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975) का 51) की धारा 8 ख की उपधारा (I) }द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक (रक्षोपाय) के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार ने दिनांक 30-6-99 की अधिसूचना संख्या 82/99 सीमा शुल्क के द्वारा कथित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष संख्या 290/ 11 के अधीन आने वाले फिनाल पर, जब कभी भी यह भारत में आयातित हो, निम्न दरों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया था:-

(क) 29 फरवरी, 2000 सहित इस तारीख तक के आयात पर 22% और

(ख) 1 मार्च, 2000 से 29 जून तक (दोनों दिन शामिल) के बीच आयात होने पर 15%

आगे कथित अधिसूचना द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ख की उपधारा (6) के खण्ड (ए) के अधीन दक्षिण अफ्रीका के अलावा अधिसूचित विकासशील देशों से फिनाल के आयातों पर अन्य बातों के साथ-साथ रक्षोपाय शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

2. रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 18 के अधीन हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिंग.(एच.ओ.सी.) मुम्बई और हर्डीलिया केमिकल्स लिंग(एच.सी.एल.) मुम्बई ने भारत में फिनाल के वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को हो रही निरंतर क्षति से बचाने हेतु भारत में फिनाल के आयात पर लगाए गए रक्षोपाय शुल्क के पुनरीक्षण के लिए मेरे समक्ष एक ग्रेटेन प्रस्तुत किए जाने पर 1 जरवरी,2001 को पुनरीक्षण का एक नोटिस जारी किया गया था और अंतिम जाँच परिणाम 16-5-2001 को जारी किए गए थे और इन्हें 20-6-2001 को भारत के रापजत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 18 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ख की उपधारा (1) और (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उपर्युक्त जॉच परिणामों पर पुनरीक्षण में विचार करने के पश्चात भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 73/2001 सीमा शुल्क दिनांक 28 जून, 2001 द्वारा भारत में फिनाल के आयात पर निम्नानुसार रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया है :-

- (क) 10% जब आयात 30 जून,2001 से 29-6-2002 तक हो (दोनों दिन शामिल) और
- (ख) 7% जब आयात 30 जून, 2002 से 29 जून, 2003 तक हो (दोनों दिन शामिल)।

कथित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 ख की उपधारा (6) के खंड (क) के अधीन विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित देशों से फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क से भी छूट दी है।

3. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को सूचित किया गया है कि अप्रैल से सितम्बर,2001 के शुरू में ब्राजील, चीन,कोरिया,सिंगापुर एवं दक्षिण अफ्रीका से दिनांक 14-12-98 की अधिसूचना संख्या 103/98- सीमा शुल्क में सूचीबद्ध कुछ संघटित विकासशील देशों से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ख के अधीन कथित दिनांक 28 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 73/2001- सीमा शुल्क में विस्तारित लाभों की छूट के लिए उनको पात्र बनाया जा सके। इसके लिए उनका भारत में फिनाल का आयात अनुबद्ध डीमिनिमस स्तर से कहीं अधिक है। यह भी कहा गया है कि केवल जुलाई, 2001 में दक्षिण अफ्रीका एवं सिंगापुर से 3551 टन का आयात हुआ जो वर्ष 2000-2001 के दौरान फिनाल के कुल आयात का 13% से भी अधिक निकलता है। यह अनुरोध किया गया है कि इन विकासशील देशों से होने वाले आयातों पर उपलब्ध रक्षोपाय शुल्क की छूट को समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा, जो प्रेषित माल शुल्क से बच गया है उन पर भी रक्षोपाय शुल्क लगाना चाहिए।

4. मामले की जॉच की गई थी और प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत हुआ था कि उपरोक्त विकासशील देशों से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ख के अधीन निरूपित फिनाल का आयात ढी. मिनिमस स्तर से अधिक था। तदनुसार पुनरीक्षण कार्रवाई शुरू करने का निश्चय किया गया था। पुनरीक्षण का उद्देश्य यह था कि क्या ऐसे अधिसूचित विकासशील देशों से फिनाल के आयात पर वे देश रक्षोपाय शुल्क की अदायगी से छूट के पात्र थे।

(ख) प्रक्रिया:-

क्या अधिसूचित विकासशील देशों से भारत में फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क की छूट दी जाए इस पर विचार करने के लिए पुनरीक्षण का नोटिस 22-10-2001 को जारी किया गया था एवं दिनांक 23-10-2001 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था। सभी ज्ञात इच्छुक पक्षों को नोटिस की प्रति उनके दृष्टिकोण जानने के लिए भेजी गई थी एवं दस्तावेजी साक्ष्य 29-11-2001 तक जमा कराने हेतु कहा गया था यथा:-

घरेलू उत्पादक

- (i) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिंग (एच.ओ.सी.एल.), मुम्बई
- (ii) हड्डीलिया केमिकल्स लिंग (एच.सी.एल.), मुम्बई
- (iii) नेवेली लिग्नाइट रासपोरेशन, तमिलनाडु

आयातक/उपभोक्ता उद्योग

- (1) सी.जे.शाह एंड कम्पनी, मुम्बई
- (2) हरेश कुमार एंड कम्पनी, मुम्बई
- (3) विन्मार इन्टरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिंग, मुम्बई
- (4) सोनकमल इंटरप्राइजेज, मुम्बई
- (5) खेतान ब्रदर्स, मुम्बई
- (6) एक्सप्रो, इंडिया, मुम्बई
- (7) केसर पेट्रो प्राडक्ट्स लिंग, मुम्बई
- (8) बेकलाइट हाइलाम लिंग, हैदराबाद
- (9) गार्गी हटनस एल्बर्ट्स प्राइवेट लिंग, मुम्बई
- (10) एल्टा लेबोरेट्रीज लिंग, दादर मुम्बई
- (11) यूनाइटेड फार्मोरस लिंग, मुम्बई

- (12) कलर केम लिंग, बाल्कम, थाने
- (13) किटप्लाई इंडस्ट्रीज, कलकत्ता
- (14) रोमित रेसिन्स प्राइवेट लिंग, पनवेल
- (15) बिलाग इंडस्ट्रीज, वापी
- (16) यूनाइटेट मेटाकेम, पूणे
- (17) मार्वल थर्मोसेट्स, प्राइवेट लिंग, मुम्बई
- (18) दौराला आर्गेनिक्स लिंग, नई दिल्ली
- (19) सेंचुरी लेमिनेटिंग कम्पनी लिंग, नई दिल्ली
- (20) फोसेको इंडिया लिंग, पूणे
- (21) शिनेकटेडी स्पेसिलिटिज एशिया लिंग, मुम्बई

निर्यातक

- (1) फिनालकेमी जी.एम.बी.एच., जर्मनी
- (2) एनीकेम, इटली
- (3) जार्जिया गल्फ कारपोरेशन, यू.एस.ए.
- (4) मित्सुई केमिकल्स, टोकयो/मित्सुई एंड कम्पनी लिंग, सिंगापुर
- (5) कुम्हो केमिकल कम्पनी, सियोल कोरिया
- (6) ताईवान प्रोसपेरिटी केमिकल कम्पनी, ताईवान
- (7) मेरिसोल, दक्षिण अफ्रीका, (मेरिकेम सासोल)
- (8) कोल्मार पेट्रोकेमिकल्स ए.जी. स्विटजरलैंड
- (9) आई.सी.सी. केमिकल्स कारपोरेशन, न्यूयार्क
- (10) तोसोह कारपोरेशन, तोकयो
- (11) फोरमोसा प्लास्टिक्स कारपोरेशन, ताईवान
- (12) ट्रिकोन इनर्जी लिंग, यू.एस.ए.

समुद्रपार संगठन

- (i) केमिकल्स सेफ्टी मैनेजमेंट सेंटर, जापान केमिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन-जेसीआईए टोकयो 100, जापान
- (ii) केमिकल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (सी ए आई ए) आकलैंड पार्क 2006 दक्षिण अफ्रीका
- (iii) कोरियन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एसोशिएशन (के पी आई ए) चोगनो-कू, सियोल कोरिया

- (iv) पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन आफ ताईवान (पी.आई.ए.टी) सेक्शन 4, छुटुंग, सिंचु ताईवान
- (v) केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोशिएशन (सी.एम.ए) वर्जानिया 22209 , यू एस ए
- (vi) वरबंद, दर केमिस्केन इंडस्ट्री - वी सी एल जर्मनी

भारतीय संगठन

1. सोसाइटी आफ थर्मोसेटिंग इंडस्ट्रीज, मुम्बई
2. इंडियन लेमिनेट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोशिएशन, मुम्बई
3. इंडियन केमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोशिएशन, मुम्बई
4. आल इंडिया एसोशिएशन आफ इंडस्ट्रीज, मुम्बई

2. पुनरीक्षण के नोटिस की एक प्रति सभी निर्यातक देशों यथा बेल्जियम, चीन, ताइपे, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, डी.पी.आर, कोरिया आर पी, दी नीदरलैंड, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, यू.के, यू.एस.ए, और यूरोपीय समुदाय भारत में यूरोपीय उच्चायुक्त के प्रतिनिधियों को उनके नई दिल्ली में उच्चायुक्तों/एंबेसी के माध्यम से भेजी गई थी ।

3. दिनांक 22.10.2001 के नोटिस के जबाब निम्नलिखित पक्षों से प्राप्त हुए

घरेलू उत्पादक

1. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लि., मुम्बई
2. हर्डीलिया केमिकल्स लि., मुम्बई

आयातक/उपभोक्ता उद्योग

1. केसर पेट्रो प्राउक्ट्स लि., मुम्बई
2. फोसेको इंडिया लि., पुणे

निर्यातक

1. मित्सुई फिनाल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर
2. इनिओस फिनाल जी एम बी एच एण्ड क. के जी, डयूचलैंड जर्मनी
3. इनिकेम पैसिफिक लिमिटेड, इटली

भारतीय संगठन

(1) आल इंडिया एसोसिएशन आफ इंडस्ट्रीज, मुम्बई

ग. निर्यातकों के दृष्टिकोण

निर्यातकों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे दिए गए हैं :-

(क) मित्सुइ फिनाल सिंगापुर पीटीई लि. सिंगापुर

(i) फिनाल एक देश के समस्त उद्योग की शक्ति दर्शाने के लिए एक बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है। 20 वीं सदी के आरम्भ से फिनाल व्यापारिक रूप से प्रयोग किया जाता है और अब फिनाल पूरे विश्व में उपभोग किया जाता है तथा इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है।

(ii) भारत में दो उत्पादकों द्वारा जितने भी फिनाल का उत्पादन किया जाता है, भारत में फिनाल की मांग उससे अधिक है और भारत में इसकी अनुमानित मांग लगभग 9000 से 10,000 टन प्रतिमाह है जबकि उत्पादन लगभग 5000 टन से 6000 टन प्रतिमाह है।

(iii) उनको नहीं लगता कि आयातों से घरेलू उत्पादकों को क्षति हो रही है और वास्तव में विदेशी फिनाल आपूर्तक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिरप्दित्यक कीमतों पर इस कमी को पूरा करते हैं।

(iv) सिंगापुर से फिनाल का वर्धित आयात भारत में ग्राहकों के हित के अनुसार होगा।

(v) स्वच्छ व्यापार भाव की दृष्टि से रक्षोपाय की छूट की धारा को बनाए रखने की आवश्यकता है और भारत के राष्ट्रीय हित में जब भी संभव हो, रक्षोपाय शुल्क को अपने आप समाप्त कर दिया जाए।

(ख) इनिओस फिनाल, जर्मनी

शुल्क संरचना में कोई विषमता नहीं होनी चाहिए और वे इस क्षेत्र में समान स्तर की आशा करते हैं। उन्होंने कुछ विकाराशील देशों से प्राप्त होने वाले फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क छूट को रद्द करने और जो माल शुल्क अधिरोपण से बच गए हैं उन पर भी रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का अनुरोध किया है।

(ग) इनिकेम पैसिफिक लि., इटली

(i) वे भारतीय बाजार को फिनाल के मुख्य अथवा नियमित आपूर्तक नहीं रहे और उन्होंने यूरोपियन कीमतों पर बहुत कम मात्रा में भारत को फिनाल निर्यात किया। उन्होंने उनके द्वारा किए गए निर्यात पर रक्षोपाय शुल्क से छूट के लिए अनुरोध किया है।

(घ) आयातकर्ता/प्रयोगकर्ता उद्योगों के दृष्टिकोण

- (क) मैसर्स केसर पैट्रोप्रोडक्ट्स लि., मुम्बई
- (ख) मैसर्स फोसैको इण्डिया लि., पुणे

उन्होंने मोटे तौर पर निम्नलिखित बातें कहीं हैं -

(क) नोटिस के अनुसार पुनरीक्षण का उद्देश्य यह है कि ऐसे अधिसूचित विकासशील देशों से फिनाल के आयात करने पर क्या वे देश रक्षोपाय शुल्क की अदायगी से छूट के पात्र हैं? उनकी दृष्टि से पुनरीक्षण के प्रयोजन का पुनर्निरूपण आवश्यक है और आरम्भ से आँकने के लिए इसे व्यापक करने का अनुरोध किया है कि क्या वास्तव में भविष्य में फिनाल के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क संरक्षण जारी रखने के लिए यह न्यायोचित है।

(ख) फिनाल विनिर्माताओं में से एक हरडीलिया केमिकल्स लि. नामक कम्पनी की मूल स्थिति में, इसका प्रबन्धन और नियन्त्रण एक बहु-राष्ट्रीय कार्पोरेशन, शिनेकटेडी कार्पोरेशन, यूएसए के हाथ में चले जाने के कारण, परिवर्तन हुआ है जो कि भारत में और भारत से बाहर फिनाल के मुख्य उपभोक्ता हैं। देश की 37.5% फिनाल की विनिर्माण क्षमता बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कब्जे में है और देश में अन्य फिनाल उपभोक्ताओं की पहुँच से बाहर हो गया है।

(ग) फिनाल की विनिर्माण लागत में सबसे महत्वपूर्ण घटक जैसे कि इसके कच्चे माल की कीमतों में बढ़ा परिवर्तन आया है जो कि फिनाल विनिर्माताओं के अनुकूल है। कच्चे माल और फरनेस आयल की कीमतें काफी कम हो गई हैं।

(घ) दोनों विनिर्माता लगातार बहुत लाभ कमा रहे हैं और अपने अन्य उत्पादों के नुकसान को भी उन फिनाल उपभोक्ताओं से वसूल करके पूरा कर रहे हैं जो कि अपने संचालनों के बन्द होने की गंभीर आशंका का सामना कर रहे हैं।

(ङ.) जिन आधारों पर घरेलू उत्पादकों ने रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था वे आज नहीं हैं।

(च) अप्रैल से सितम्बर, 2001 के आरम्भ की अवधि के दौरान देश के विनिर्माताओं में से एक विनिर्माता के कम उत्पादन के कारण फिनाल का आयात अधिक था और यह एक अस्थायी विषय है जो विकासशील देशों से आयातों पर स्वीकृत छूट के पुनरीक्षण का संकेत नहीं देता। उसी अवधि के दौरान अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, 2001 तक फिनाल के अन्य विनिर्माता, जैसे कि हरडीलिया जो अपनी 17,000 मी.टन (92% की प्रयोग क्षमता) की यथानुपात क्षमता के मुकाबले 15600 मी.टन फिनाल का उत्पादन कर सका है अर्थात् उन्होंने किसी विपणन के दबाव का सामना नहीं किया जो यह दर्शाता है कि एच और सी एल के उत्पादन में कमी उनकी अपनी कठिनाई के कारण हुई न कि विपणन के कारण ।

(छ) वर्ष 2000-01 में स्वयं हरडीलिया ने 2222 मी.टन तक फिनाल आयात किया जो वर्ष 1999-2000 में उनके 951 मी.टन के आयात से कहीं अधिक था। निर्यात प्रयोजनों के कारण चाहे आयात निःशुल्क हो, फिर भी हरडीलिया को लगभग 70 मी.टन अमरीकी डालर समुद्री भाड़ा और निकासी और भंडारण इत्यादि अन्य लागतों की अदायगी करनी पड़ी थी।

(ज) हरडीलिया ने अपने उत्पादनों को प्रयोग करने की बजाय फिनाल के आयात को अधिक लाभकारी पाया है जिसका अर्थ है कि उनके अपने उत्पादनों पर लाभ समुद्री भाड़े निकासी इत्यादि के खर्चों की लागत से कहीं अधिक हैं।

(झ) हरडीलिया फिनाल पर आधारित उत्पादों का निर्यात करती है जैसे कि डोडिसिल तथा अन्य अल्किल फिनाल, आइसोफोरोन तथा डायसिटोन अल्कोहल जो कि शिनेक्टेडी द्वारा विनिर्माण किए जाने वाले उत्पाद हैं। शिनेक्टेडी द्वारा हरडीलिया को हाथ में लिए जाने से यह डर है कि इन फिनाल आधारित उत्पादों का बड़ी मात्रा में भारत में विनिर्माण किया जाएगा और उनका निर्यात होगा। इसके फलस्वरूप देश में अन्य उपभोक्ताओं को फिनाल इस हद तक कम उपलब्ध होगा कि फिनाल के लिए मांग और आपूर्ति की दूरी को बढ़ा देगा।

(ण) इसमें बिल्कुल भी कोई औचित्य नहीं है कि विकासशील देशों से फिनाल के आयातों पर स्वीकृत छूट को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि देश में फिनाल के कम उत्पादन के कारण फिनाल के आयात अधिक हुए। अतः फिनाल उपभोक्ताओं को बड़ा धक्का लगता यदि विकासशील देशों ने आयात करने की सुविधा न होती। दिनांक 16.5.2001 के अंतिम निष्कर्षों में यह स्वीकार किया गया था कि प्रथम वर्ष में 12,000 मी.टन और दूसरे वर्ष में 12,500 मी.टन की मांग और आपूर्ति में दूरी थी इसलिए इतनी मात्रा के लिए रक्षोपाय शुल्क से छूट की सिफारिश की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन दूरियों की सीमा तक रक्षोपाय शुल्क के बिना फिनाल के आयात को अनुमति देना आवश्यक है और इसलिए कम से कम उपरोक्त दूरियों की सीमा तक दिनांक 28-6-2001 की अधिसूचना संख्या 73/2001 में स्वीकृत छूट को हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

उपरोक्त के अलावा पूर्व पुनरीक्षण के दौरान मैसर्स केसर पैट्रोप्रोडक्ट्स द्वारा की गई उनकी प्रस्तुतियों की उन्होंने पुनरावृत्ति की है ।

ड़ संगठन के दृष्टिकोण

आल इण्डिया एसोशिएशन आफ इण्डस्ट्रीज, मुम्बई

(i) हाल ही में दिनांक 28 जून, 2001 की एक सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 73/2001 सीमा शुल्क जारी की गई है जो फिनाल पर दो वर्षों के लिए रक्षोपाय शुल्क अवधि को बढ़ाती है । यह निर्णय हरडीलिया कैमिकल्स लि. द्वारा किए गए आवेदन पर आधारित था जिसके कारण एचसीएल को बड़ा लाभ हुआ ।

(ii) शिनेकटेडी (इण्डिया) जो कि शिनेकटेडी, यूएसए की एक सहायक कम्पनी है के द्वारा हरडीलिया कैमिकल्स होलडिंग्स लि. (एच सी एल) के शेयर अर्जित करने के लिए जारी सार्वजनिक आफर दस्तावेज में यह देखा जा सकता है कि इस सार्वजनिक आफर के द्वारा वास्तव में शिनेकटेडी इण्डिया एचसीएल के सम्पूर्ण अंशों की मालिक बन जाएगी । एचसीएल देश में दो फिनाल विनिर्माताओं में से एक है । शिनेकटेडी विश्व में फिनाल के बड़े उपभोक्ताओं में एक है और जिसने पहले ही भारत में नोनिल फिनाल विनिर्माण करने के लिए सुविधा स्थापित कर ली है जो कि देश में अब एक अकेली विनिर्माता है ।

(iii) यह महत्वपूर्ण है कि एक बार शिनेकटेडी द्वारा एचसीएल का अधिग्रहण एक बार पूरा हो गया तो इसका फिनाल पर दोनों तरह से विनिर्माता और बड़ा उपभोक्ता के रूप में एकाधिकारिक नियन्त्रण हो जाएगा जिसका देश में फिनाल आधारित उद्योगों के हितों के विरुद्ध दुरुपयोग की संभावना है जो कि मुख्यतः छोटे और मध्यम क्षेत्र के हैं और जो अपने तैयार उत्पादों के आयात शुल्क में कमी के कारण अपने संयत्रों को बड़ी कठिनता से चलाए रखने के लिए प्रयासरत हैं ।

(iv) उपरोक्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में यह एक सुदृढ़ मामला है कि भारत में फिनाल आधारित उद्योगों द्वारा दायर की गई आपत्तियों के बावजूद दिनांक 28.06.2001 की अधिसूचना के अधीन फिनाल पर अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क के मुद्दे के विरुद्ध एक बार जाँच कर ली जाए ।

(v) केंद्रीय सरकार ने शुल्क में दिनांक 30 जून, 1999 की अधिसूचना सं. 82/99- सीमा शुल्क के द्वारा फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया था । यहाँ अधिसूचना महानिदेशक (रक्षोपाय) के दिनांक 12-5-1999 के अन्तिम निष्कर्षों पर आधारित थी । कथित अन्तिम निष्कर्षों में महानिदेशक (रक्षोपाय)) द्वारा यह लिखा गया था कि एचसीएल ने अभिवेदन किया है कि वे लागत में कभी हासिल करने के लिए फिनाल संयंत्र में कुछ संशोधन करेंगे जिसके द्वारा रक्षोपाय शुल्क की अवधि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी । इस प्रकार के आश्वासनों के बावजूद एचसीएल ने महानिदेशक रक्षोपाय को

29 जून, 2001 के बाद रक्षोपाय के पुनरीक्षण के लिए एक सयुक्त आवेदन दिया था । फिनाल प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा आपत्तियाँ करने के बावजूद, महानिदेशक (रक्षोपाय) ने दिनाक 16 मई, 2001 के अपने अन्तिम निष्कर्षों के द्वारा कम दरों पर फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क की समयावधि बढ़ाने की सिफारिश की थी और यह सिफारिश की थी कि फिनाल की कुछ मात्रा को इस प्रकार के शुल्क से छूट दी जाए क्योंकि उस स्तर तक के फिनाल के आयात देश में मॉग और आपूर्ति में दूरी के कारण अपरिहार्य समझे गए । सरकार ने फिर भी अपनी 28 जून, 2001 की अधिसूचना स 73/2001 - सीमा शुल्क द्वारा मात्रात्मक छूट की अनुमति के बिना कम दरों पर 30 जून, 2001 से 29 जून, 2003 तक फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क अवधि को बढ़ा दिया । लेकिन यह शर्त लगाई कि अग्रिम लाइसेस के अधीन आयात और विकासशील देशों से आयातों पर ही इस रक्षोपाय शुल्क की छूट होगी ।

(vi) यह ध्यान देना अर्थपूर्ण है कि शिनेक्टेडी इण्डिया ने स्वयं महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास यह कहते हुए अपनी यह आपत्ति दायर की थी कि रक्षोपाय शुल्क अवधि को बढ़ाया गया तो यह फिनाल आधारित विनिर्मित उत्पादों को अप्रतिस्पर्धात्मक बना देगी ।

(vii) शिनेक्टेडी द्वारा एचसीएल के अधिग्रहण के कारण फिनाल बाजार की स्थिति पूरी तरह बदल गई थी जिस पर महानिदेशक रक्षोपाय ने पुनरीक्षण में विचार नहीं किया था इसलिए भविष्य में फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क जारी रहने का कोई औचित्य नहीं है । देश में फिनाल आधारित उद्योगों के हितों के संरक्षण के लिए भविष्य के लिए फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क को समाप्त करने के लिए सारे मामले का पुनरीक्षण किया जाए ।

क्योंकि यह घरेलू फिनाल विनिर्माण पर एकाधिकारिक नियन्त्रण का सामना करने के लिए और लघु स्तर के फिनाल आधारित उद्योगों के हित में फिनाल आधारित उद्योगों को ऐसे देशों रो आयातों के किसी भी अवसर से बचित कर देगी इसलिए दिनाक 28 जून, 2001 की अधिसूचना स 73/2001-सीमा शुल्क का यह पुनरीक्षण जब तक अनिर्णीत है, कथित अधिसूचना में विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित देशों से फिनाल के आयातों पर दी गई छूट को किसी भी परिस्थितियों में हटाया नहीं जाना चाहिए ताकि वे कार्यक्षेत्र का एक स्तर पा सके और वे अपने अस्तित्व पर अन्तिम प्रहार न झेले ।

(च) घरेलू उत्पादकों के दृष्टिकोण

घरेलू उत्पादकों के निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए हैं -

(i) रक्षोपाय शुल्क की अवधि के विस्तार का उद्देश्य फिनाल के आयात के स्तर पर अकुश था जिसने घरेलू फिनाल उत्पादक उद्योग को गभीर क्षति पहुँचाई थी । तथापि अवधि के विस्तार के बावजूद उल्टा ही हुआ । आयात में सारभूत वृद्धि हुई । विस्तारित अवधि (अर्थात् 1 जुलाई से 4 अक्टूबर, 2001) की प्रथम तिमाही में आयात अचानक गिरती कीमतों पर पूरे वर्ष 2000-2001 में 26,442 टन की तुलना

में 23,044 टन था । इन आयातों का एक सारभूत हिस्सा (7899 टन 1 जुलाई, 2001 से 4 अक्टूबर 2001 तक) विकासशील देशों जैसे सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से आयात हुआ । इन दोनों देशों का प्रत्येक का शेयर 3% से अधिक होते हुए भी वर्तमान में इन देशों से आयात पर कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लिया जा रहा है (छूट प्रदान किए जाने के कारण) ।

(ii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 ख के अनुसार विकासशील देशों से आयात पर रक्षोपाय शुल्क तब तक उदग्रहीत नहीं है जब तक उस विशेष देश से आयात का शेयर कुल आयात के 3% से कम हो । रक्षोपाय शुल्क के उदग्रहण से छूट तब तक प्रदान की गई है जब तक आयात का शेयर उपरोक्त वर्णित स्तर को पार नहीं करता । सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका, भारत सरकार की अधिरूचना स 103/98 दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 के अधीन शामिल किए गए विकासशील देशों की सूची में आते हैं । इनमें से, दक्षिण अफ्रीका हमेशा फिनाल का एक बड़ा उत्पादक रहा है और भारत को फिनाल का एक मुख्य निर्यातक है । दक्षिण अफ्रीका (एक विकासशील देश) से आयात का शेयर 33.80% तक ऊँचा था (वर्ष 1998-99 में) यह शेयर (अप्रैल, 1999 से मार्च 2001 तक की अवधि के दौरान) केवल दक्षिण अफ्रीका से फिनाल आयात के लिए रक्षोपाय शुल्क प्रतिरोधक होने के कारण 4% तक कम हो गया । इस प्रकार की छूट संभवतः दी गई थी क्योंकि, बहुत संक्षिप्त अवधि थी (अर्थात अप्रैल, 2000 से मार्च 2001 जब रक्षोपाय शुल्क लागू था) के लिए दक्षिण अफ्रीका से फिनाल आयात का शेयर 3% से कम था । 1 अप्रैल, 2001 से 4 अक्टूबर, 2001 की लगभग छः महीनों की अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीका से 2349 टन फिनाल के आयात की सूचना दी गई है । अगर उस अवधि के लिए कुल आयात 30,380 टन (सभी स्त्रोतों से) के साथ इन आंकड़ों की तुलना की जाए तो दक्षिण अफ्रीका का शेयर लगभग 7.73% (जो कि 3% के डी- मीनिमिस स्तर से कहीं अधिक है ।) बैठता है । यदि केवल 27,872 टन प्रतिपूर्ष को विगत दो वर्षों (1999-2000 एवं 2000-2001) के कुल औसत वार्षिक आयात से इन छः महीनों के आयात के आंकड़ों की तुलना की जाए तो दक्षिण अफ्रीका से शेयर लगभग 8.4% बैठता है । पिछले वित्तीय वर्ष के आयात (26,442 टन का) के प्रतिशत के रूप में दक्षिण अफ्रीका का शेयर 8.8% से ऊपर बैठता है । दक्षिण अफ्रीका से फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क तुरंत एवं तत्काल प्रभाव से लगाया जाना चाहिए ।

(iii) पहले, 1999 में, दक्षिण अफ्रीका के अलावा किसी विकासशील देश से फिनाल आयात की कोई मुख्य संभावना नहीं थी । तथापि सिंगापुर अब भारत में फिनाल के एक मुख्य निर्यातक के रूप में उभरा है क्योंकि मित्सुई ने जुलाई, 2001 के दौरान सिंगापुर में अपना एक बड़ा फिनाल संयंत्र शुरू कर दिया है । सिंगापुर में फिनाल के लिए कोई विशेष स्थानीय बाजार नहीं है (सिवाय इसके कि कुछ मात्रा जो कि बिसफिनाल-ए के विनिर्माण में प्रयुक्त होती है) और मित्सुई के लिए सबसे करीबी बाजार भारत है । इसलिए इस देश से भारत में फिनाल का आयात अंधाधुंध कम कीमतों एवं अत्यधिक मात्रा में होना शुरू हो गया । सिंगापुर में (जुलाई 2001 में) फिनाल का बड़ी क्षमता में उत्पादन शुरू करने के एक तिंगाही के अन्दर सिंगापुर से आयात की बाढ़ सी आ गई जिसका शेयर पहले ही कुल आयात के 3% से कहीं अधिक पार कर चुका है । 1 जुलाई 2001 से 4 अक्टूबर, 2001 के बीच की अवधि के दौरान सिंगापुर रा भारतीय तटों पर अत्यधिक बड़े फिनाल के पार्सल पहुँचे हैं । 1 जुलाई 2001 से शुरू लगभग तीन महीनों

की अवधि के दौरान सिंगापुर से 7066 टन फिनाल के आयात की सूचना दी गई है । यदि उस अवधि के लिए कुल आयात (सभी स्त्रोतों से) 23044 टन के साथ इन आँकड़ों की तुलना की जाती है तो सिंगापुर का शेयर लगभग 30.66% बैठता है (जो कि 3% के डी मिनिमिस स्तर से कहीं ऊपर है) यदि विंगत दो वर्षों (1999-2000 एवं 2000-2001) के कुल 27,872 टन प्रति वर्ष के औसत वार्षिक आँकड़ों के साथ इन तीन महीनों के आयात आँकड़ों की तुलना की जाए तो सिंगापुर का शेयर लगभग 25% से ऊपर बैठता है । पिछले वित्तीय वर्ष के आयात (26,442 टन का) के प्रतिशत के रूप में सिंगापुर का शेयर 26% से ऊपर बैठता है ।

(4) दक्षिण अफ्रीका एवं सिंगापुर देशों से प्रत्येक का फिनाल का आयात डी-मिनिमिस स्तर पार कर चुका है, उन्होंने भारत सरकार से सिंगापुर एवं दक्षिण अफ्रीका से होने वाले फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने संबंधी अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया है ।

(5) कम कीमतों एवं बिना रक्षोपाय शुल्क के इन दो देशों से आयात की बाढ़ से घरेलू फिनाल विनिर्माताओं को गंभीर क्षति पहुंची है । माल सूची बढ़ गई हैं । वास्तव में, सिंगापुर से आयात की बाढ़ शुरू हुई, इसके पश्चात ही फिनाल का भंडारण बढ़ने लगा एवं दोनों कम्पनियों का संयुक्त भंडारण अगस्त, 2001 तक 2861 टन था । हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. की सुविधा बंद कर दी गई थी (4 से 19 सितम्बर 2001 के बीच) एवं 28 अक्टूबर 2001 को 1009 टन (ढेर जमा पैकड़ संयुक्त) के बड़े भंडारण के कारण हड्डीलिया को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है ।

(6) अप्रैल 2000 से मार्च 2001 के दौरान विद्यमान कीमतों से भी कम कीमतों पर फिनाल का आयात हुआ । इसलिए दोनों भारतीय फिनाल विनिर्माण कम्पनियों को अपने फिनाल के मूल्य कम करने पड़े ।

(7) उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से फिनाल के आयात पर अनन्तिम आधार पर रक्षोपाय शुल्क के उद्ग्रहण के अलावा सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से फिनाल आयात पर रक्षोपाय शुल्क उद्ग्रहण पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाने हेतु आवेदन किया है ।

(8) निष्कर्ष

मैंने मामले के रिकार्ड एवं सभी इच्छुक पक्षों, जिनमें घरेलू उत्पादक, उपभोक्ताओं/आयातक एवं निर्यातक शामिल है, द्वारा प्रस्तुत जवाबों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है । विभिन्न पक्षों द्वारा क्राफी संख्या में मुद्दे उठाए गए हैं, जो कि वर्तमान प्रक्रिया के क्षेत्राधिकार से सीधे संबंधित नहीं है, जिन्हें कि पुनरीक्षण के नोटिस में पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है । यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अधिसूचित विकासशील देशों से फिनाल का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8

ख के अधीन निर्धारित डि मिनिमिस स्तर से कहीं अधिक था और इच्छुक पक्षों को अपने ज्ञात दृष्टिकोण देने एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। पुनरीक्षण का उद्देश्य इन देशों से फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने को ग्राह्य बनाने हेतु फिनाल के कुल आयात में विकासशील देशों के शेयर निर्धारित करने का था।

जहाँ तक वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 (सितम्बर 2001 तक) के दौरान भारत में फिनाल के आयात का संबंध है यह महसूस किया जाता है कि नीचे सारणी में दर्शाए गए देशों ने कथित अवधि के दौरान भारत में फिनाल का निर्यात किया। वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 की अवधि के लिए आँकड़े डीजीसीआईएस कलकत्ता से लिए गए हैं और वर्ष 2000-2001 के एवं 2001-02 (सितम्बर 2001 तक) के आँकड़े आवेदकों ने प्रस्तुत किए हैं जिनको कि डीजीसीआईएस और कांडला सीमा शुल्क के साथ सत्यापित किया गया है। सत्यापित आँकड़ों के आधार पर भारत में फिनाल का कुल आयात में विभिन्न देशों/क्षेत्रों का शेयर नीचे सारणी के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

देश/क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02 (9/01)	
	मात्रा	%शेयर	मात्रा	%शेयर	मात्रा	%शेयर	मात्रा	%शेयर
चीन पी आर	7.000	0.03	117.667	0.40	-	-	40.000	0.16
यूरोपीय समुदाय	85.735	0.34	16493.150	56.29	7348.301	27.79	8059.231	31.16
इंजराइल	-	-	20.500	0.07	-	-	-	-
जापान	5911.450	23.45	849.716	2.90	1014.139	3.83	76.400	0.30
कोरिया आर पी	9762.106	38.72	16.000	0.05	-	-	-	-
मलेशिया	-	-	-	-	-	-	1570.000	6.07
मेक्सिको	-	-	100.000	0.34	-	-	-	-
रूस	36.000	0.14	895.046	3.05	-	-	-	-
दक्षिण अफ्रीका	8522.457	33.80	2165.344	7.40	374.000	1.41	2020.124	7.81
सिंगापुर	16.000	0.06	72.600	0.25	41.400	0.16	8071.483	31.21
स्विटजरलैंड	0.100	-	28.000	0.09	-	-	-	-
सऊदी अरब	-	-	108.000	0.37	-	-	296.400	1.15
ताईवान	809.505	3.21	231.850	0.79	3550.420	13.43	3779.886	14.62
अमेरिका	62.645	0.25	8204.216	28.00	14114.732	53.38	1947.000	7.52
कुल	25212.999	100	29302.089	100	26442.992	100	25860.524	100

यहाँ सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ख के प्रावधानों को पुनर्प्रस्तुत करना उपयुक्त है जो कि सरकार को कथित धारा के प्रावधानों के अनुसरण में रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति प्रदत्त करते हैं।

“यदि केन्द्र सरकार ऐसी जाँच करने के बाद जैसा कि वह उचित समझती है संतुष्ट हो जाए कि कोई वर्तु भारत में इतनी वर्धित मात्रा एवं ऐसी परिस्थितियों के अधीन आयात की गई है जिससे कि घरेलू उद्योगों को गंभीर क्षति पहुँच रही है या इसकी आशंका है, तो वह शासकीय गजट में अधिसूचना के द्वारा उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क लगा सकती है।

बशर्ते कि ऐसा कोई भी शुल्क विकासशील देशों से आयातित वस्तु पर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उस वस्तु का उस देश से आयात का हिस्सा 3% से अधिक नहीं बढ़ता अन्यथा जहाँ एक से अधिक ऐसे विकासशील देशों से वस्तु का आयात होता है तो जब तक कि उस वस्तु का भारत में उन देशों से आयात कुल मिलाकर 9% से अधिक नहीं होता ।

उपरोक्त सारिणी से यह महसूस किया जाता है कि 2001-2002 (अप्रैल-सितम्बर) के प्रथमार्ध के दौरान निम्नलिखित विकासशील देशों (दिनांक 14-12-1998 की अधिसूचना संख्या 103/98-सीमा शुल्क के अधीन अधिसूचित अधिसूचना संख्या 62/99 दिनांक 13-5-99 द्वारा यथा संशोधित) से भारत में फिनाल का आयात 3% या इससे अधिक रहा है :-

मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर

तदनुसार यह संस्तुत किया जाता है कि इन अधिसूचित विकासशील देशों से भारत में फिनाल का आयात फिनाल पर उदग्रहणीय रक्षोपाय शुल्क के अध्याधीन होगा ।

उन अधिसूचित विकासशील देशों, जिनका प्रत्येक का भारत में फिनाल के आयात में शेयर 3% से कम है सभी का समग्रलूप में 9% नहीं होता तो यह संस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार के विकासशील देशों से फिनाल का आयात रक्षोपाय शुल्क के अधीन नहीं होगा ।

[फा. सं. एस जी/आई एन बी/2/98-(पुनरीक्षण)]

आर. के गुप्ता, महानिदेशक

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2001

Sub : Review of Safeguard duty imposition on imports of Phenol into India from notified developing countries under Rule 18 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter referred to as the SGD Rules) read with Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975—final findings.

GSR. 50(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof.

A. Introduction

The notice initiating investigation concerning import of Phenol into India was issued on 02.02.99 under Rule 6 of the SGD Rules. Final findings were issued under Rule 11(1) of the said Rules, (published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II-Section-3-Sub-section (i)) on 11.06.99, recommending safeguard duty to be imposed @ of 22% advalorem during the 1st year and @ of 15% advalorem during the 2nd year on imports of Phenol into India being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the serious injury threatened to be caused by the increased imports of Phenol. In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975(51 of 1975) read with Rules 12 and 14 of the SGD Rules and based on the final findings of the Director General (Safeguards), the Central Government vide Notification No.82/99-Customs dated 30th June, 1999 imposed on Phenol, falling under sub-heading number 2907.11 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, when imported into India, a safeguard duty at the rate of;

- (a) 22% when imported upto and inclusive of the 29th day of February, 2000; and
- (b) 15% when imported from the 1st of March, 2000 to 29th day of June, 2001 (both days inclusive).

Further the said notification exempted, inter alia, levy of safeguard duty on imports of Phenol from notified developing countries under Clause (a) of sub-section (6) of Section 8B of Customs Tariff Act 1975, other than South Africa.

2. On an application filed before me under Rule 18 of the SGD Rules by Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOC), Mumbai and Herdillia Chemicals Ltd. (HCL), Mumbai for review of Safeguard duty imposed on imports of Phenol into India to protect the domestic producers of Phenol against continued serious injury caused by the increased imports of Phenol into India, a notice of review was issued on 1st January 2001 and final findings were issued on 16.05.2001 and was published in the Gazette of India, Extraordinary on 20.06.2001

In exercise of powers conferred by sub-section (1) and (4) of section 8B of the Customs Tariff Act 1975, read with rule 18 of the SGD Rules, the Central Government vide Notification No. 73/2001-CUSTOMS dated 28th June 2001, after considering the aforesaid final findings in review, imposed safeguard duty on imports of Phenol into India as under:

- (a) 10%, when imported from the 30th day of June, 2001 to the 29th day of June, 2002 (both days inclusive); and
- (b) 7%, when imported from the 30th day of June, 2002 to the 29th day of June, 2003 (both days inclusive).

The notification also exempted levy of safeguard duty on imports of Phenol made from countries notified as developing countries under clause (a) of sub-section (6) of section 8B of the said Customs Tariff Act.

3. It has been informed to the Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi that the imports of Phenol into India during April to early September 2001 from Brazil, China, Korea, Singapore and South Africa constituting some of the notified developing countries listed in Notification No.103/98-Customs dated 14.12.98 are much more than the de-minimis level stipulated under Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 to make them eligible for availing the exemption benefits extended by the aforesaid Notification No. 73/2001-CUSTOMS dated 28th June 2001. It has also been stated that imports from South Africa and Singapore in July 2001 alone was to the extent of 3551 tonnes, which worked out to more than 13% of the total imports of Phenol during the year 2000-01. It has been requested that the exemption from safeguard duty available to imports originating from these developing countries may be revoked. Further, the consignments that have escaped the levy, should also be subjected to safeguard duty.

4. The matter was examined and it appeared *prima facie* the imports of Phenol from the aforementioned notified developing countries were more than the de-minimis level stipulated under Section 8B of the Customs Tariff Act 1975. Accordingly it was decided to initiate review proceedings. The purpose of the review was to determine whether such notified developing countries were eligible to the exemption from payment of safeguard duty on imports of Phenol from these countries.

B. Procedure

The Notice of Review to consider whether safeguard duty on imports of Phenol into India from notified developing countries should be exempted was issued on 22.10.2001 and was published in the Gazette of India, Extraordinary on 23.10.2001. A copy of the Notice was sent to all known interested parties to make their views known and submit documentary evidence by 29th November 2001 namely:-

Domestic Producers

- (i) Hindustan Organic Chemicals Ltd (HOCL), Mumbai
- (ii) Herdillia Chemicals Ltd. (HCL), Mumbai
- (iii) Neyveli Lignite Corporation, Tamilnadu.

Importers/User Industries

- (i) C.J.Shah & Company, Mumbai
- (ii) Haresh Kumar & Company, Mumbai
- (iii) Vinmar International India Pvt. Ltd., Mumbai
- (iv) Sonkamal Enterprises, Mumbai
- (v) Khetan Brothers, Mumbai
- (vi) Xpro India, Mumbai
- (vii) Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai
- (viii) Bakelite Hylam Ltd., Hyderabad
- (ix) Gargi Huttenes Albertus Private Limited, Mumbai
- (x) Alta Laboratories Ltd., Dadar, Mumbai
- (xi) United Phosphorus Limited, Mumbai
- (xii) Colour Chem Limited, Balkum, Thane
- (xiii) Kitply Industries, Calcutta
- (xiv) Romit Resins Pvt. Ltd., Panvel
- (xv) Bilag Industries, Vapi
- (xvi) United Metachem, Pune
- (xvii) Marvel Thermosets P. Ltd., Mumbai
- (xviii) Daurala Organics Ltd., New Delhi.
- (xix) Century Laminating Co., Ltd., New Delhi
- (xx) Foseco India Ltd., Pune
- (xxi) Schnectady Specialities Asia Ltd., Mumbai

Exporters

- (i) Phenolchemie GmbH, Germany
- (ii) Enichem, Italy
- (iii) Georgia Gulf Corporation, U.S.A.
- (iv) Mitsui Chemicals, Tokyo/Mitsui & Co. Ltd., Singapore
- (v) Kumho Chemical Company, Seoul, Korea
- (vi) Taiwan Prosperity Chemical Company, Taiwan
- (vii) Merisol, South Africa, (Merichem Sasol)

- (viii) Kolmar Petrochemicals AG, Switzerland.
- (ix) ICC Chemical Corporation, New York,
- (x) Tosoh Corporation, Tokyo
- (xi) Formosa Plastics Corporation, Taiwan
- (xii) Tricon Energy Ltd., U.S.A.

Overseas Associations

- (i) Chemical Safety Management Centre, Japan Chemical Industry Association-JCIA, Tokyo 100, Japan.
- (ii) Chemical and Allied Industries Association -(CAIA) Auckland Park 2006, South Africa.
- (iii) Korean Petrochemical Industry Association -(KPIA) Chongno-ku, Seoul, Korea.
- (iv) Petrochemical Industry Association of Taiwan (PIAT) Section 4, Chutung, Hsinchu, Taiwan.
- (v) Chemical Manufacturers Association (CMA) Virginia-22209, USA
- (vi) Verband der Chemischen Industrie - VCI Germany

Indian Associations

- (i) Society of Thermosetting Industries, Mumbai
- (ii) Indian Laminates Manufacturers Association, Mumbai
- (iii) Indian Chemical Manufacturers Association, Mumbai
- (iv) All India Association of Industries, Mumbai

2. A copy of the notice of review was also sent to the governments of exporting countries through their High Commissions/Embassies in New Delhi namely Belgium, Chinese Taipei, Germany, Italy, Japan, Korea DPR, Korea RP, the Netherlands, Russia, Singapore, South Africa, U.K., USA and to the European Union, Delegation of the European Commission in India, New Delhi.

3. Replies to the Notice dated 22.10.2001 were received from the following parties:-

Domestic Producers

- (i) Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai
- (ii) Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai

Importers/User Industries

- (i) Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai
- (ii) Foseco India Ltd. Pune

Exporters

- (i) Mitsui Phenol Singapore Pte. Ltd., Singapore
- (ii) Ineos Phenol GmbH & Co.KG, Deutschland, Germany
- (iii) EniChem Pacific Limited, Italy.

Indian Associations

- (i) All India Association of Industries, Mumbai

C. Views of Exporters

The following main points have been made by the exporters:

(a) Mitsui Phenol Singapore PTE. Ltd., Singapore

- (i) Phenol acts as a barometer indicating the strength of the overall industry of a country. Phenol has been used commercially from the beginning of 20th century, and now Phenol is consumed by many industries around the world and the demand continues to grow.
- (ii) Phenol demand in India exceeds the total output of the two producers in India and the estimated demand in India is about 9000 to 10000 tonnes per month as against production of about 5000 to 6000 tonnes per month.
- (iii) They do not think the domestic producers are damaged by imports and in fact the foreign Phenol suppliers cover the shortage at internationally competitive prices.
- (iv) The increase of Phenol imports from Singapore would be in accordance with the interest of customer in India .
- (v) The exemption clause of the safeguard needs to be retained in view of the spirit of the fair trade and that the safeguard duty itself should be abolished as soon as possible for the national interest of India.

(b) Ineos Phenol, Germany

- (i) There should be no disparities in the duty structure and they expect a uniform level playing field. They have requested to revoke the safeguard duty **exemption** on imports of Phenol originating from few of the developing countries and also levy safeguard duty on the consignments which have escaped the levy.

(c) EniChem Pacific Ltd., Italy

- (i) They have never been a major or a regular supplier of Phenol to the Indian market and only very small quantities have been exported to India at European prices. They have requested for exemption from safeguard duty on export made by them.

D. Views of Importers/User industries

- (a) **M/s. Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai**
(b) **M/s. Foseco India Ltd., Pune**

They have stated broadly the following:

- (a) As per the notice, the purpose of the review is stated to be to determine whether such notified developing countries are eligible to the exemption for payment of safeguard duty on imports of Phenol from these countries. In their view it is necessary to redefine the scope of the review and to widen it to determine ab-initio whether basically there is proper justification for continuing the safeguard duty protection on imports of Phenol in future.
- (b) There is a basic change in the status of one of the manufacturers of Phenol namely Herdillia Chemicals Limited due to its management and control being taken over by a Multi-national Corporation, Schenectady Corporation, USA which is a major consumer of Phenol in India and outside India 37.5% of the country's Phenol manufacturing capacity has become captive to the multinational and gone out of reach of other Phenol consumers in the country.
- (c) The most important component of manufacturing cost of Phenol namely the cost of its raw materials has undergone a major change which is favourable to the Phenol manufacturers. The prices of raw materials and furnace oil have substantially come down.
- (d) Both the manufacturers of Phenol are continuing to make high profits and covering up losses in their other product lines at the cost of consumers of Phenol who are facing a serious threat of closure of their operations.
- (e) The grounds on which the domestic producers applied for extension of period of SGD do not exist today.
- (f) The imports of Phenol during the period from April to early September 2001 were more because of less production by one of the manufacturers of Phenol (HOCL) in the country and is a temporary phenomenon which does not call for review of exemption granted to imports from developing countries. During the same period i.e. from April to September 2001 the other manufacturer of Phenol namely Herdillia could produce 15600 MT of Phenol against its pro-rata capacity of 17000 MT (capacity utilisation of 92%) thus did not face any marketing constraint which shows that HOCL's reduction in production was due to its own problem other than marketing.
- (g) Herdillia itself imported Phenol to the extent of 2222 MT in the year 2000-01 which was much higher than their import of 951 MT in the year 1999-2000. Though the imports may be duty free being for export purposes, Herdillia had to pay ocean freight of about US\$ 70 MT and other costs of clearing, storage etc.

(h) Herdillia finds it worthwhile to import Phenol rather than use its own production which means that the margin on its own production is more than the cost on ocean freight, clearance charges etc.

(i) Herdillia exports the products based on Phenol viz. Dodecyl & other alkyl Phenol, Isophorone & Diacetone Alcohol which are the products manufactured by Schenectady. With the take over of Herdillia by Schenectady it is feared that huge quantities of these Phenol-based products shall be manufactured in India and exported. This will result in less availability of Phenol to other consumers in the country to that extent and widen the demand supply gap for Phenol.

(j) There is no justification at all for removing the exemption granted to imports of Phenol made from developing countries since imports of Phenol were higher due to less production of Phenol in the country. Thus the Phenol consumers would have suffered a major set back if the benefit of importing from developing countries would not have been there. In the final findings dated 16.05.2001 it was acknowledged that there is a demand/supply gap of 12000 MT in the first year and 12,500 MT in the second year and hence these quantities were recommended to be exempted from safeguard duty. It is submitted that to the extent of these gaps, it is necessary to permit import of Phenol free of SGD and hence there is no case to remove the exemption granted in the Notification No.73/2001 dated 28.6.2001 for imports from notified developing countries, at least to the extent of the above gaps.

In addition to the above M/s Kesar Petroproducts have reiterated their submissions made by them during the earlier review carried out.

E. Views of the Association

The All India Association of Industries, Mumbai

(i) Recently, a Customs Notification bearing No. 73/2001 Customs dated 28th June 2001 has been issued which extends the safeguard duty period on Phenol by two years. This decision was based on the application made by Herdillia Chemicals Ltd. which has resulted in major gain to HCL.

(ii) In the Public Offer document issued by Schenectady (India) a subsidiary of Schenectady USA for acquiring shares of Herdillia Chemicals Holdings Limited (HCL) it may be seen that by this public offer Schenectady India will virtually be the sole shareholder of the HCL. HCL is one of the two manufacturers of Phenol in the country. Schenectady is one of the largest consumers of Phenol in the world and has already established the facility for manufacturing nonyl phenol in India of which it is now the sole manufacturer in the country.

(iii) It will be appreciated that once the acquisition of HCL by Schenectady is complete it will have monopolistic control on Phenol both as its manufacturers

and a major consumer which is likely to be misused against the interest of Phenol based industries in the country which are mainly in small and medium sector and are struggling to continue to run their plants with great difficulties due to reduction in import duty of its own end products.

(iv) In the background of the above developments there is a strong case to examine once again the issue of Safeguard duty imposed on Phenol under the Notification dated 28.06.2001, in spite of objections filed by all the Phenol based industries in India.

(v) The Central Government had originally imposed safeguard duty on Phenol vide Notification No. 82/99-Customs dated 30th June 1999. This notification was based on the final findings of the Director General (Safeguard) dated 12th May 1999. In the said final findings it was noted by DG(Safeguard) that HCL had represented that they would carry out certain modifications in the Phenol plant to achieve reduction in cost by which the extension of Safeguard duty will not be required. In spite of such assurance HCL made a joint application of DG Safeguard for review of Safeguard duty beyond 29th June 2001. In spite of objections raised by Phenol users, DG Safeguard, by its final findings dated 16th May 2001 recommended extension of Safeguard duty on Phenol at lower rates and recommended that certain quantity of Phenol be exempted from such duties since imports of Phenol upto that level were considered unavoidable due to supply and demand gap in the country. The government by its notification No.73-2001 Customs dated 28th June 2001 however, extended the Safeguard duty on Phenol at lower rates for the period from 30th June 2001 to 29th June 2003 without allowing quantitative exemption but providing that the import under advance licence as well as imports from developing countries will be exempted from such safeguard duty.

(vi) It is significant to note that Schenectady India itself had filed its objection with DG (Safeguard) to extension of Safeguard duty on Phenol stating that it would make manufacture of Phenol based products uncompetitive.

(vii) Due to Schenectady's acquisition of HCL the situation in Phenol market is completely changed which was not covered by the review of DG Safeguard & hence there is no justification for continuing the Safeguard duty on Phenol in future. The entire matter be reviewed for discontinuing the Safeguard duty on Phenol for future to protect the interest of Phenol based industries in the country.

(viii) Pending such review of Notification No.73-2001 Customs dated 28th June 2001 the exemptions included in the said notification for the imports of Phenol from the countries notified as developing countries may not be removed under any circumstances since it will deprive the Phenol based industries of any opportunity to importing from such countries to face the monopolistic control on domestic Phenol manufacture and in the interest of the small scale Phenol based industries so that they get a level playing ground and do not suffer a final blow to their existence.

F. Views of domestic producers

The domestic producers have made the following main points:

- (i) The purpose of the extension of the period of Safeguard Duty was to keep in check the level of imports of Phenol that had caused Serious Injury to the domestic Phenol producing industry. However, despite the extension of the period, contrary has happened. Imports have increased significantly. The imports in approximately the first quarter of the extended period (i.e. 1st July to 4th October 2001) were as high as 23,044 Tons as against 26,442 Tons in the whole year 2000-01 with sharply declining prices. A significant portion of these imports (7899 Tons from 1st July 2001 - 4th October 2001) has come in from 'developing countries' such as Singapore and South Africa. Presently, on imports from these countries, no Safeguard Duty is being levied (due to the exemption granted) despite the share of each of these two countries being individually more than 3%.
- (ii) As per Section 8B of the Customs Tariff Act, Safeguard Duty is not leviable on imports from a developing country only so long as the share of imports from that specific country is less than 3% of the total imports. The exemptions for levy of Safeguard Duty have been granted only so long as the share of imports does not cross the levels mentioned above. The countries Singapore and South Africa fall in the list of developing nations covered in the Notification of the Government of India No. 103/ 98 dated 14th December 1998. Of these, South Africa has always been a large producer of Phenol and a major exporter of Phenol to India. The share of imports from South Africa (a developing country) was as high as 33.80 % (in the year 1998-99). The share came down to 4% (during the period April 1999 to March 2001) only due to Safeguard Duty being a deterrent for Phenol imports from South Africa. Such exemption was granted possibly because, for a very brief period (i.e. April 2000 to March 2001, when Safeguard Duty was in force), the share of Phenol imports from South Africa was less than 3%. During the approximate six month period of 1st April 2001 to 4th October 2001, imports from South Africa are reported to be 2349 Tons. If this figure is compared with total imports (from all sources) 30,380 Tons for the same period, the share of South Africa works out to 7.73% (which is well above the de-minimis level of 3%). Even if the six month import figure is compared with total average annual imports of previous two years (1999-2000 and 2000-01) of 27,872 TPA, the share of South Africa works out to over 8.4%. As percentage of last fiscal year's import (of 26,442 Tons), the share of South Africa works out to over 8.8%. Safeguard Duty should be levied on Phenol imports from South Africa immediately and with retrospective effect.
- (iii) Earlier, in 1999, there was no major possibility of Phenol import from any developing country other than South Africa. However, Singapore is now emerging as a major exporter of Phenol to India as Mitsui has commissioned its large Phenol plant in Singapore during July 2001. There is no significant local

market for Phenol in Singapore (except for some quantities being consumed for manufacture of Bisphenol-A) and the nearest market for this Mitsui facility is India. Exports from this country to India have therefore started coming in at drastically low prices and in large quantities. Within a quarter of commissioning of a large capacity for Phenol in Singapore (in July 2001), there has been a flood of imports from Singapore, the share of which has already crossed well beyond 3% of the total imports. Large Phenol parcels have arrived on the Indian shores from Singapore during the period between 1st July 2001 to 4th October 2001. During the approximate three month period starting from 1st July 2001, imports from Singapore are reported to be 7066 Tons. If this figure is compared with total imports (from all sources) of 23,044 Tons for the same period, the share of Singapore works out to 30.66% (which is well above the de-minimis level of 3%). Even if the three month import figure is compared with total average annual imports of previous two years (1999-2000 and 2000-01) of 27,872 TPA, the share of Singapore works out to over 25%. As percentage of last fiscal year's import (of 26,442 Tons), the share of Singapore works out to over 26%.

(iv) The imports of Phenol from South Africa and Singapore have individually crossed the de-minimis levels, they have requested the Govt. of India to issue a notification making Safeguard Duty applicable on import of Phenol from Singapore and South Africa.

(v) The flood of imports from these two countries at low prices and without attracting Safeguard Duty has caused grave harm to the domestic Phenol manufacturers. Inventories have piled up. In fact, soon after the flood of imports from Singapore started, the stocks of Phenol mounted and the combined stock of both companies put together was 2861 Tons towards the end of August 2001. The facility of Hindustan Organic Chemicals Ltd. was shut down (between 4th to 19th September 2001) and Herdillia may have to follow suit very soon in view of high stocks of Phenol of 1009 Tons (bulk plus packed combined) as on 28th October 2001.

(vi) Imports of Phenol have come in at still lower prices than the prices prevailing during April 2000 to March 2001. Both the Indian Phenol manufacturing companies have therefore had to reduce their Phenol prices.

(vii) They have also requested to levy Safeguard Duty on Phenol imports from South Africa and Singapore at least on a provisional basis besides levy of Safeguard Duty on Phenol imports from Singapore and South Africa with retrospective effect.

G. Findings

I have carefully gone through the case records and replies filed by all the interested parties including the domestic producers, users/importers and exporters. A number of issues have been raised by various parties, which have no direct bearing on the scope of the present proceedings which has been

made amply clear in the notice of review. It was clearly mentioned that it appeared *prima facie* the imports of Phenol from the notified developing countries were more than the de-minimis level stipulated under Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 and the interested parties were asked to make their views known and submit documentary evidence. The purpose of the review was to determine the share of developing countries in the total imports of Phenol eligible to the exemption from payment of safeguard duty on imports of Phenol from these countries.

As regards the imports of Phenol into India during the period 1998-99, 1999-2000, 2000-01 and 2001-02(upto September 2001) it is observed that the countries mentioned in the Table below exported Phenol to India during the said period. The data for the period 1998-99 and 1999-2000 has been taken from DGCIS Calcutta and for the period 2000-01 and 2001-02 (upto September 2001) is based on the data furnished by the applicants which has been duly verified with the DGCIS and Kandla Customs. On the basis of the verified data, the share of various Countries/ Territories in the total imports of Phenol into India is determined as per table below :

Share of various countries in Imports of Phenol into India Imports in MT

Country/territory	1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02(9/01)	
	Quantity	%age share						
China PR	7.000	0.03	117.667	0.40	-	-	40.000	0.16
European Community	85.735	0.34	16493.150	56.29	7348.301	27.79	8059.231	31.16
Israel	-	-	20.500	0.07	-	-	--	--
Japan	5911.450	23.45	849.716	2.90	1014.139	3.83	76.400	0.30
Korea RP	9762.106	38.72	16.000	0.05	-	-	---	---
Malaysia	-	-	-	-	-	-	1570.000	6.07
Mexico	-	-	100.000	0.34	-	-	--	--
Russia	36.000	0.14	895.046	3.05	-	-	--	--
South Africa	8522.457	33.80	2165.344	7.40	374.000	1.41	2020.124	7.81
Singapore	16.000	0.06	72.600	0.25	41.400	0.16	8071.483	31.21
Switzerland	0.100	-	28.000	0.09	-	-	--	--
Saudi Arabia	-	-	108.000	0.37	-	-	296.400	1.15
Taiwan	809.505	3.21	231.850	0.79	3550.420	13.43	3779.886	14.62
USA	62.645	0.25	8204.216	28.00	14114.732	53.38	1947.000	7.52
Total	25212.999	100	29302.089	100	26442.992	100	25860.524	100

It is pertinent here to reproduce the provisions of Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 which empowers the Government to impose Safeguard duty in accordance with the provisions of the said section.

"If the Central Government after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury

to domestic industry, then it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article.

Provided that no such duty shall be imposed on article originating from a developing country so long as the share of imports of that article from that country does not exceed three percent or where the article is originating from more than one developing countries then, so long as the aggregate of the imports from all such countries taken together does not exceed nine percent of the total imports of that article into India.”

It is observed from the above tabulation that the share of following developing countries (notified under Notification No. 103/98 -Cus dated 14.12.1998 as amended by Notification No. 62/99 dated 13.5.99) in the import of Phenol into India during the first half of 2001-02(April- Sept.) has been 3% or more:

Malaysia, South Africa and Singapore.

Accordingly, it is recommended that imports of Phenol into India from these notified developing countries be subjected to safeguard duty leviable thereon.

The total share of notified developing countries, having individual share of less than 3% in the import of Phenol into India, does not account for 9% or more collectively and accordingly, it is recommended that imports of Phenol from such notified developing countries may not be subject to safeguard duty.

[F. No. SG/INV/2/98-(Rev.)]

R. K. GUPTA, Director General